ट्रेड वार और दुनिया

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के थमने के आसार नहीं है और यह स्थिति शीत युद्ध में बदलती जा रही है. कुछ महीने पहले तक आपसी सुलह की उम्मीद बन रही थी. साल 2018 में अमेरिका भेजे गये चीनी सामान का मूल्य 539 अरब डॉलर था. इसमें से करीब आधे पर ट्रंप प्रशासन ने शुल्क लगाया है. उसने संकेत दिया है कि बाकी बची चीजों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है. इसके जवाब में चीन ने 110 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों को शुल्क के दायरे में डाल दिया है. अमेरिका ने चीन को पिछले साल 120 बिलियन डॉलर का कुल निर्यात किया था. अमेरिका का मानना है कि इस कार्रवाई से देश में बनी चीजें चीन से आयातित सामानों से सस्ती हो सकती हैं और इससे घरेलू कारोबार को फायदा होगा. दूसरा तर्क है कि संभावित व्यापार समझौते में इससे चीन पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी. लेकिन, राष्ट्रपति ट्रंप के इस पैंतरे से भले ही चीन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, अमेरिकी व्यापार जगत भी परेशानी में है. विकसित देशों के संगठन, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ समेत अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने व्यापार युद्ध को नुकसानदेह माना है. वैश्वीकरण और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में अमेरिका और चीन जैसी शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं की आपसी तनातनी के असर से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी नहीं बच सकती है. विकसित देशों की संस्था का कहना है कि इस तनाव से दुनिया की आर्थिकी की वृद्धि 2016 के स्तर पर पहुंच सकती है, लेकिन अगर अमेरिका और चीन में शुल्कों पर सहमति बन जाती है, तो 2020 में इसका फायदा मिल सकता है. छत्तीस देशों की इस संस्था ने ट्रेड वार को कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. अनुमान है कि मौजूदा हालत में दुनिया का कुल घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की दर पिछले साल के 3.5 फीसदी से घटकर इस साल 3.2 फीसदी हो जायेगी. वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर के 3.9 फीसदी से कम होकर 2.1 फीसदी रहने का अंदेशा है, जो कि एक दशक में सबसे निचले स्तर पर है. साल 2017 में यह दर 5.5 फीसदी रही थी. अनेक देशों के लिए वृद्धि दर में मामूली कमी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है. पहले से ही यह दर इटली में शून्य, जर्मनी में 0.7 फीसदी (पिछले साल से आधा) और जापान में 0.7 फीसदी रहने का अनुमान है. जी-20 के कुछ ही देश ऐसे हैं, जो पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. इनमें ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना (पर यहां मंदी बनी रहेगी) और भारत हैं. यह संतोषजनक है कि भारत की वृद्धि दर 7.2 फीसदी रहेगी, जो कि इस देशों में सर्वाधिक है. लेकिन अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल तथा राजनीति व कूटनीति में तनाव हमारे विकास में भी बाधक बन सकते हैं. उदाहरण के तौर पर तेल की कीमतों में अस्थिरता और निर्यात घटने जैसे कारकों को लिया जा सकता है. ट्रेड वार के खात्मे के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय पहल की जरूरत है.

विकसित देशों के संगठन, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ समेत अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने व्यापार युद्ध को नुकसानदेह माना है.

कांग्रेस के लिए चुनाव के संदेश

प्रभु चावला
वरिष्ठ पत्रकार
prabhuchawla
@newindianexpress.com

कांग्रेस मर चुकी है. कांग्रेस का विचार अमर रहे! वर्ष 2019 के एग्जिट पोल ने ये दोहरा संदेश दिया है कि हालांकि राज्य विधानसभाओं तथा संसद में इस 'ग्रैंड ओल्ड पार्टी' की जगह अब काफी तंग हो चुकी है, पर भारत के सभी कोनों में इसके कार्यकर्ता जीवित तथा सक्रिय हैं. यदि 19 मई की चुनावी अटकलें नतीजों के दिन उलटी-पुलटी भी हो जायें, तो इतना तय है कि कांग्रेस केंद्र के सत्ता सोपान के प्रथम पायदान से भी मीलों दूर ही रहेगी. फिर भी, लोकतंत्र की अबूझ चालें अपना यह विशेषाधिकार तो सुरक्षित रखती ही हैं कि 23 मई के दिन कोई अदृश्य-सी भूमिगत तरंग किसी एक गांधी को सिंहासन पर आसीन कर दे.

सर्वाधिक उदार से लेकर सबसे कठोर तक किसी भी चुनावी विशेषज्ञ ने इस महान पार्टी को 90 से अधिक सीटें नहीं दी हैं. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी छोटी-बड़ी 150 से भी ज्यादा रैलियां और रोड शो करते हुए 100 दिनों से भी अधिक सड़कों पर बिताये. उनकी बहन प्रियंका पार्टी की आधिकारिक प्रचारकर्ता के रूप में अपनी प्रथम भूमिका के तहत देश के विभिन्न हिस्सों के दौरे करते हुए मोदी के जादू की काट की कोशिशें करती रहीं. पर गांधी परिवार के इन दो वारिसों द्वारा 130-वर्षीय पुरानी पार्टी पर पारिवारिक पकड़ की लोकतांत्रिक पुष्टि प्राप्त करने के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए सभी टीवी चैनल गुजरात के गौरव पर ही गौर करते दिखे. वर्ष 1989 के चुनावों में पार्टी को मिली उस अपमानजनक पराजय के पश्चात, जब महज पांच साल पहले उसे मिली चार सौ सीटों की जगह जनता ने सिर्फ दो सौ सीटें देना ही स्वीकार किया था, गांधी परिवार से कोई अन्य साउथ ब्लाक स्थित सत्ता सिंहासन पर अब तक भी आसीन न हो सका. तब से तीन दशक बीत जाने पर भी उनके द्वारा नीत पार्टी आज भी प्रासंगिक तो है, परंतु उनका पारिवारिक नाम अब अपनी चमक खो चुका है. अतीत के अपने उस रुतबे के विपरीत, जब इंदिरा गांधी किसी खंभे को भी पार्टी उम्मीदवार बनाकर उसे जीत दिला सकती थीं, अब यह परिवार केवल कांग्रेस के बूते ही अपनी सियासी पहचान कायम रख पाने में समर्थ है. सोनिया से लेकर प्रियंका तक किसी भी वर्तमान गांधी में वह चुंबकीय शक्ति नहीं रही कि वह जनता को आकृष्ट कर सके.

विरासत में मिली इस पार्टी को वे उसके सिकुड़ते आधार के बावजूद एकजुट रख पाने में तो सफल हैं, पर अब वे चुनावी विजेता नहीं रहे. अमित शाह के विपरीत, जिन्होंने पांच वर्षों से भी कम समय में भाजपा को विश्व की सबसे पड़ी पार्टी में तब्दील कर एक विश्व रिकॉर्ड रच दिया, राहुल और उनकी अनाम टीम कांग्रेस की सदस्यता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज नहीं करा सकी. राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर संगठन निष्प्रभावी तथा गुटबाजी का शिकार बना पड़ा है. संभवतः एकजुटता की इसी कमी की वजह से पार्टी अधिकतर राज्यों में भाजपा सरकार के बावजूद सरकार विरोधी भावना का लाभ न ले सकी. भाजपा के पास सर्वाधिक संख्या में सांसद तथा विधायक हैं, वह 16 राज्यों में सत्तारूढ़ है और नरेंद्र मोदी पिछले पांच वर्षों से सत्ता शीर्ष पर बने हुए हैं. इसने कांग्रेस को लगभग प्रत्येक राज्य में पटखनी दी है. टीवी एंकर का विवेक यह बताता है कि चूंकि राज्यों में कांग्रेस की सीटें दहाई के पार नहीं हैं, इसलिए वह केंद्र में भी दहाई संख्या के परे सीटें नहीं पा सकती.

राहुल गांधी को अब यह अपरिवर्तनीय वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दिल्ली एवं राज्यों में सिर्फ एक सामूहिक नेतृत्व ही कांग्रेस को भाजपा के विकल्प में तब्दील कर सकता है.

पिछले पांच सालों से कांग्रेस उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व की अपनी भूमि अपने शत्रु के हाथों हारती जा रही है. पूरे देश में दो सौ से भी अधिक सीटों पर भाजपा के साथ सीधे संघर्ष के बाद भी इसने उनमें से 150 से भी ज्यादा गंवा दिये. कांग्रेस का राजनीतिक क्षरण 1990 के दशक से शुरू हुआ, जब उसके क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपनी स्वयं की पार्टी बनाने को उससे विदा ले ली. तेलुगु देशम तथा तेलंगाना राज्य समिति जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने दक्षिण में उसे पहले ही जख्मी कर छोड़ा था. पिछले दो दशकों के दौरान यह उत्तर एवं पश्चिम में हिंदुत्व लहर के द्वारा बिलकुल हाशिये पर ला दी गयी. एक करिश्माई नेता के अभाव में पार्टी ने अल्पसंख्यकों, दलितों तथा यहां तक कि किसानों जैसे अपने पारंपरिक वोट बैंक भी गंवा दिये. वर्ष 2004 में इसे सत्ता मिली भी, तो उसकी वजह किसी नेता अथवा नारे की चुंबकीय शक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ सोनिया गांधी द्वारा दिखाया गया सौदेबाजी का वह हुनर थी, जिसके बूते कांग्रेस अवसरवादी रूप से सहानुभूति रखतीं क्षेत्रीय पार्टियों को पटा सकी. वर्ष 2004 और 2009 में पार्टी को गांधी के ठप्पे ने नहीं, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग एवं मनमोहन सिंह नीत सरकार के विश्वसनीय प्रदर्शन ने जिताया. फिर भाजपा ने वर्ष 2009 के चुनाव एलके आडवाणी जैसे एक बुजुर्ग के नेतृत्व में लड़े थे, जिनके पास युवा मतदाताओं को अपने पाले कर पाने योग्य नये विचारों से लैस कोई एजेंडा न था.

तभी राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक महानायक की भांति मोदी का अवतरण हुआ, जिनके पास आशाजनक नारे एवं देश पर लौह हाथों से शासन करने का निश्चय था. नतीजतन दिल्ली के सिंहासन तक की अपनी शानदार विजय यात्रा में मोदी को वंश मोह में पड़ी इस पार्टी से किसी प्रतीकात्मक प्रतिरोध का भी सामना नहीं करना पड़ा. कांग्रेस का पराभव उसके द्वारा स्वयं को समय के साथ परिवर्तित कर पाने की असमर्थता से पैदा होता है. यह खुद को नये विचारों और व्यक्तियों से विभूषित करने की बजाय केवल एक गांधी की जगह दूसरे को बिठाती रही है.

कांग्रेस के पास अब संतोष करने को केवल यही एक तथ्य शेष है कि कांग्रेस का विचार अब भी जिंदा है. राहुल गांधी को अब यह अपरिवर्तनीय वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दिल्ली एवं राज्यों में सिर्फ एक सामूहिक नेतृत्व ही कांग्रेस को भाजपा के विकल्प में तब्दील कर सकता है. कांग्रेस को विभिन्न राज्यों में वाम दलों द्वारा रिक्त किये गये स्थल की भरपाई करने पर गौर करना चाहिए. अब जब भारत चरम दक्षिणपंथ की ओर एक और निर्णायक करवट ले रहा है, भारत को एक बार फिर मध्यमार्गी स्थिति में लाने का तकरीबन असंभव कार्य भारत को आजादी दिलानेवाली यह पार्टी ही कर सकती है. गांधियों को भविष्य में एक बार फिर ब्रांड गांधी के पुनरोदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए.

(अनुवाद : विजय नंदन)

ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध जरूरी

डॉ अश्विनी महाजन
एसोसिएट प्रोफेसर, डीयू
ashwanimahajan@rediffmail.com

कंपनियों का धर्म लाभ है. उनको किसानों और आम लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है. जीएम फसलों को रोकना इसलिए भी जरूरी है, ताकि कैंसरकारी और जानलेवा ग्लाईफोसेट नामक रासायनिक जहर से देश को बचाया जा सके.

बीते 14 मई, 2019 को अमेरिका के ऑकलैंड की एक जूरी ने मोनसेंटो के 'राउंडअप' नामक खरपतवार से एक दंपत्ति को कैंसर होने के कारण कंपनी को दो अरब डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है. मोनसेंटो पर इस प्रकार के हर्जाने का यह तीसरा मामला है. लगातार तीन मुकदमों में न्यायालयों ने मोनसेंटो के 'राउंडअप' को कैंसरकारी होने के दावे को मंजूर करते हुए, पीड़ितों को भारी हर्जाना देने के आदेश सुनाये हैं. कंपनी की मुश्किलें यहीं खत्म होनेवाली नहीं हैं. ऐसे हजारों मामले अमेरिका के कई न्यायालयों में विचाराधीन हैं. पिछले साल बेयर कंपनी ने मोनसेंटो का अधिग्रहण कर लिया था और अब मोनसेंटो कंपनी बेयर-मोनसेंटो कहलाती है.

वर्ष 2015 में डब्ल्यूएचओ की 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर' (आईएआरसी) ने अपने शोध में पाया था कि 'ग्लाईफोसेट', जो कि 'राउंडअप' नामक खरपतवार नाशक का एक अहम हिस्सा है, नॉन हाडकिंन लाईफोना (कैंसर) का जोखिम बढ़ाता है और साथ ही डीएनए एवं गुणसूत्र को भी क्षति पहुंचाता है. ग्यारह देशों के 17 विशेषज्ञ 3-10 मार्च, 2015 को डब्ल्यूएचओ के तत्वाधान में मिले थे और यह निष्कर्ष दिया था. आईएआरसी का निष्कर्ष था कि ग्लाईफोसेट और उसके योगों का जीन विषाक्तता का सबूत है. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आईएनआरसी ने एक हजार अध्ययनों की समीक्षा की.

एक तरफ जहां राउंडअप के उपयोग के कारण कैंसर होने के मामले न केवल प्रकाश में आ रहे हैं, बल्कि न्यायालयों ने भी इस बाबत पीड़ितों को राहत देने का काम किया है. आज दुनियाभर में कैंसर व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है. एक ताजा शोध के अनुसार ग्लाईफोसेट के कारण कैंसर होने का खतरा 41 प्रतिशत बढ़ जाता है, वहीं दुनियाभर में कैंसर का बढ़ना राउंडअप के कहर को प्रमाणित करता है.

जहां दुनियाभर में लोग इससे प्रभावित हैं, वहीं ग्लाईफोसेट निर्माता कंपनियां यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं. हर बार न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने के बावजूद वे अपील-दर-अपील करने में पीछे नहीं हटतीं. कारण यह है कि उनका सारा कारोबार ही इन खरपतवार नाशकों पर आधारित जीएम फसलों पर टिका है. दुनिया में 1974 से लेकर 2014 तक कुल 8.6 अरब किलो ग्लाईफोसेट का उपयोग हो चुका था. 1995 में जहां ग्लाईफोसेट का उपयोग मात्र 510 लाख किलो था, 2014 में यह बढ़कर 7,500 लाख किलो हो गया, यानी 15 गुना वृद्धि. भारत में भी 2014 में 8.7 लाख किलो ग्लाईफोसेट का इस्तेमाल हुआ.

फसल उगाने के लिए खरपतवारों को नष्ट करना जरूरी होता है. खरपतवार दो प्रकार से हटाये जा सकते हैं, एक मानवीय श्रम से और दूसरे खरपतवार नाशकों द्वारा. चूंकि नाशकों द्वारा यह काम सस्ते में हो जाता है, किसान खरपतवार नाशकों का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें इन रसायनों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों के बारे में नहीं पता. अमेरिका में न्यायालयों द्वारा दिये गये फैसलों से यह बात सामने आयी है कि ये कंपनियां किसानों को ग्लाईफोसेट के खतरों से आगाह नहीं करती हैं.

मोनसेंटो और बेयर सरीखी कंपनियां दुनिया भर में जीएम फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं. हाल ही में भारत में बीज कंपनियों ने गैरकानूनी रूप से खरपतवार सुहाता बीटी कपास को बाजार में उतार दिया. एक मोटे अनुमान के अनुसार एक लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि पर एचटीबीटी कपास उगायी जा रही है. समझा जा सकता है कि यह काम देश में ग्लाईफोसेट/राउंडअप का बाजार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. इन कंपनियों का धर्म लाभ है. उनको किसानों और आम लोगों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है. जीएम फसलों के आगमन को रोकना इसलिए भी जरूरी है, ताकि इस कैंसरकारी और जानलेवा ग्लाईफोसेट नामक रासायनिक जहर से देश को बचाया जा सके.

साल 2015 में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध लगा. साल 2017 में फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, लॅग्जमबर्ग, स्लोवेनिया एवं माल्टा ने यूरोपीय संघ में ग्लाईफोसेट के इस्तेमाल के खतरों पर चिंता व्यक्त की थी और उसके बाद प्रतिबंध लगाने का सिलसिला शुरू हुआ. अन्य कई देशों ने पूरी तरह या कुछ मात्रा में ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है.

भारत के कई राज्यों में भी ग्लाईफोसेट को प्रतिबंधित करने के प्रयास हुए हैं. अक्तूबर 2018 में पंजाब में और फरवरी 2019 में केरल में ग्लाईफोसेट की बिक्री पर रोक लगायी गयी. महाराष्ट्र में भी ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास चल रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कई राज्यों में इस प्रतिबंध को यह कहकर निरस्त करने की मांग हो रही है कि किसी भी कृषि रसायन को पंजीकृत करने या प्रतिबंधित करने का काम केंद्र सरकार का है. दुर्भाग्य से अभी तक केंद्र सरकार ने ग्लाईफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की है.

प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने ग्लाईफोसेट के उपयोग की अनुमति केवल चाय बगानों और गैर-कृषि क्षेत्रों में दी है और जिन राज्यों में चाय बगान नहीं है, वहां इसे प्रतिबंधित करने में कोई रुकावट नहीं है. आवश्यकता इस बात की है कि देश और विश्व में ग्लाईफोसेट के कैंसरकारी होने और देश में कैंसर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से इस जानलेवा रसायन पर प्रतिबंध लगाये, ताकि कैंसर की महामारी को फैलने से रोका जा सके.

बोधि वृक्ष

जब प्रेम होता है

प्रेम के बिना आप अपने कर्म की संपूर्णता को नहीं जान सकते, क्योंकि प्रेम ही है, जो आज आदमी को बचा सकता है. यह विडंबना है कि कोई प्रेम में नहीं है. आप वास्तव में उतने सहज नहीं रह गये हैं, जितना होना चाहिए. क्योंकि आप दुनियां को सुधारने, संवारने, जिम्मेदारियों, प्रतिष्ठा, सामने वाले से कुछ हटकर करने से, कुछ विशेष होने से सरोकार रखे हुए हैं. दूसरों के नाम पर आप अपने स्वार्थों के गर्त में डूबे हैं, आप अपने ही घोंघेनुमा कवच में समाये हुए हैं. तो फिर प्रश्न है कि प्रेम क्या है? हम यह चर्चा नहीं कर रहे कि प्रेम को क्या होना चाहिए? हम यह देख रहे हैं कि वह क्या है, जिसे हम प्रेम कहते हैं. आप कहते हैं कि मैं फलां से प्यार करता हैं, पर मैं नहीं जानता कि आपका प्रेम क्या है? मुझे संदेह है कि आप किसी भी चीज से प्यार प्रेम करते हों. क्या आप प्रेम शब्द का अर्थ भी जानते हैं? क्या प्रेम आमोद-प्रमोद या मजा है? क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति प्रेम कर सकता है? इस समय संसार में जितने भी प्रेम दिखाने की चीजें हैं, यह सब महत्वाकांक्षाओं, आक्रामकता, इच्छाओं के ही अवयव हैं. हर व्यक्ति प्रतियोगिता में जी रहा है. तो क्या एक व्यक्ति जो दुनिया के दौड़ में शामिल हो, वह प्रेम में हो सकता है? अच्छे जॉब, बेहतर पद, अच्छा घर, महान विचार, अपनी सुस्पष्ट छवि बनाने में लगे हैं. क्या यह सब प्रेम है? क्या आप तब प्रेम कर सकते हैं, जब आप यह सब अत्याचार संपन्न करते गुजर रहे हों, जब आप अपनी ही पत्नी या पति या बच्चों पर प्रभुत्व जमा रहे हों? जब आप ताकत या शक्ति की खोज में लगे हों? तब क्या प्रेम की कोई संभावना बचती है? तो जो भी प्रेम नहीं है, उस सब को नकारते और अस्वीकार करते हुए हम जहां पहुंचते हैं, वही प्रेम होता है. आपको उन सबको अस्वीकार या नकारना होगा, जो प्रेम नहीं है. जब प्रेम और सौंदर्य आपके मन में होता है, तब आप जो भी करते हैं, वह लयबद्ध होता है, विधिसम्मत होता है. यदि आप जानते हैं कि प्रेम कैसे करना है, तब आप कुछ भी करें, यह अवश्य ही सभी समस्याओं का हल बन जाता है.

जे कृष्णमूर्ति

आपके पत्र

इवीएम पर सवाल

लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही एक बार फिर से इवीएम को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है. यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है. इसके पहले भी इवीएम को सवालों के घेरे में रखा गया है. आज इवीएम से चुनाव शुरू कराने के लगभग 18 वर्षों के बाद भी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाये जा रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब नतीजे आपके पक्ष में हों, तो इवीएम सही और जब नतीजे आपके पक्ष में न हों, तो इवीएम को ही गलत ठहराया जाता है. देश के नागरिक होने के नाते हमें अपनी सरकार चुनने का हक है. इवीएम को गलत बता कर देश के नागरिकों के मत का निरादर करना सही नहीं है. विपक्षी पार्टियों से आग्रह है कि वे अपनी हार का जिम्मा इवीएम को देने के बजाय जनमत का आदर करें और लोकतंत्र का सम्मान करें.

कन्हाई लाल, रांची

पानी का गहराता संकट

गोड्डा जिले के ललमटिया थाना के अंतर्गत आने वाले लगभग 25 गांवों में पानी का संकट दिनोंदिन गहराता जा रहा है. रोलडीह, बलिया, बभनिया, लोचिन्ता, बेल्डीहा, जैसे गांवों में पानी का भयावह संकट छाया हुआ है. पीने के पानी तक का इंतजाम बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन न तो प्रशासन और न सरकार ही इस ओर ध्यान दे रही है. यह संकट रातोंरात नहीं पैदा हुआ है. लगभग पांच वर्षों से इस इलाके में ठीक से बारिश नहीं हुई है. पिछले दो वर्षों से तो खेती ही बंद हो गयी है और अब पीने के लिए भी लोगों के पास पानी की बेहद कमी है. गांवों के सभी कुएं सूख चुके हैं. कुछेक में दो-तीन दिन बाद थोड़ा सा पानी निकल आता है जिससे गांव के लोगों का जिंदा रहना संभव हो पा रहा है. समय रहते अगर प्रशासन एवं सरकार ने कोई सुध नहीं ली तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है.

संदीप सोरेन, गोड्डा

आयोग की आलोचना

पूर्व राष्ट्रपति भारतरत्न प्रणब मुखर्जी ने हाल में ही एक पुस्तक के विमोचन के अवसर में चुनाव आयोग की तारीफ की. उन्होंने 2019 का चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की सराहना भी की. यह भी कहा कि प्रथम आयुक्त सुकुमार सेन से लेकर मौजूदा आयुक्त सुनील अरोड़ा तक ने अच्छे काम किये. इन विचारों से सभी सहमत होंगे, मगर जब प्रणब दा जब यह कहते हैं - आप मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना नहीं कर सकते, उनके इस कथन से किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक सहमत नहीं हो सकते. आलोचना करना, भिन्न विचार रखना ही तो लोकतंत्र की बुनियाद है. वरना चुनाव आयोगों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी. इस बार आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कई नेताओं के बोल बिगड़े हुए थे. कुछ पर कार्रवाई हुई. मगर पंथ प्रधान एवं पार्टी अध्यक्ष को क्लीनचिट दिया गया. इससे विपक्ष या आलोचक और तीन में से एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी अप्रसन्नता जाहिर की है. ऐसी स्थिति के लिए आयोग की तो आलोचना होनी ही चाहिए.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

कुछ अलग

जरूरी है पर्यावरणीय संतुलन

शफक महजबीन
टिप्पणीकार
mahjabeenshafaq@gmail.com

हम इंसानों ने अपने सुख-सुविधाओं के लिए जिस तरह दूसरे जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का दोहन कर रहे हैं, वह हमारी जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा रहा है. उदाहरण के लिए गिद्ध को ही लें. कुछ साल पहले ज्यादा दूध निकालने के लिए गायों और भैंसों को एस्प्रिन डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जाने लगा, ताकि उनकी मांसपेशियां ढीली हो जायें और वे दूध छोड़ दें. जब इन गायों और भैंसों की उम्र खत्म हुई और इनके मृत शरीर को गिद्धों ने खाया, तो डाइक्लोफेनेक का जहर उनके शरीर में फैलने लगा और धीरे-धीरे गिद्ध मरने लगे. आज गिद्ध कहीं खोजे से भी नहीं मिलते. हमने दूध का उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन गिद्धों को खत्म कर जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया.

अमेरिकी राजनेता स्टीवर्ट उदल ने कहा था- 'हवा, पानी, जंगल और जानवर को बचानेवाली योजनाएं दरअसल मनुष्य को बचाने की योजनाएं हैं.' हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारे जीवन के लिए प्रकृति एक उपहार है, इसलिए हमें सभी प्रकार के जीव-जंतु, मिट्टी, पेड़, पानी, नदी और सभी प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करना चाहिए. गौरतलब है कि कल 22 मई को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया. इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी.

जैव विविधता दिवस का अर्थ है सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच सबके जीवन का चलते रहना. जैव विविधता का संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैव विविधता नष्ट हुई, तो हमारा जीवन संकट में आ जायेगा. बाढ़, सूखा, तूफान, भूस्खलन आदि के खतरे बढ़ेंगे. पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है. आज लाखों जीव-जंतुओं की प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है. साल 1911 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता मौरिस मेटरलिंक ने कहा था- 'अगर मधुमक्खी दुनिया से खत्म हो जाये, तो मनुष्य के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ चार साल बचेंगे.' क्या यह जरूरी नहीं कि हम मधुमक्खी के साथ अन्य जीवों का संरक्षण करें?

कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे अनेक कीट प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं. कीटनाशकों के बेतहाशा प्रयोग से कई फसलों की किस्में भी नष्ट हुई हैं. जैसे हमारे देश में चावल की अस्सी हजार किस्मों में से अब कुछ ही किस्में बची हैं. रोजाना पेड़ काटे जा रहे हैं और नदियों की सदानीरा व्यवस्था खत्म हो रही है, जिससे पानी की समस्या बढ़ रही है. यह ग्लोबल वार्मिंग का भी अहम कारण है, जिससे पृथ्वी पर तापमान का स्तर बढ़ता जा रहा है.

भारत के अधिकतर गांवों में आज भी लोग लकड़ियां जलाते हैं. पशुपालन को बढ़ावा देकर और गोबर गैस संयंत्र लगाकर लकड़ी काटने से बचा जा सकता है. जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जो भूमि को बंजर होने से बचाने का बेहतरीन उपाय है. इस तरह अन्य कई उपायों से पृथ्वी के जीवन को विनाश से बचाने की हम सार्थक कोशिश कर सकते हैं.

देश दुनिया से

चुनाव से तय होगा ईयू के भविष्य का रास्ता

यूरोपीय संसद के चुनावों से यूरोपीय संघ के भविष्य का रास्ता तय होनेवाला है. यूरोपीय संसद में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक खेमे के नेता मानफ्रेड वेबर ने एक महीने पहले संसद में कहा था कि आगामी 26 मई को होनेवाले चुनाव से इस पूरे महाद्वीप का भविष्य तय होना है. वेबर खुद भी 'यूरोपियन पीपल्स पार्टी' के उम्मीदवारों की सूची में शीर्ष पर हैं. हर खेमे के उम्मीदवार आनेवाले यूरोपीय चुनावों को लगभग इसी तरह का महत्व दे रहे हैं. वेबर तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं. उनके विचार में इस बार लड़ाई सीधे-सीधे यूरोप-समर्थकों और राष्ट्रवादियों के बीच है. उनका मानना है कि आज हम जिस यूरोप में रहते हैं, वह एक अच्छा यूरोप है और राष्ट्रवादियों को इसे बर्बाद नहीं करने दिया जायेगा. इन चुनावों में दिख रहे यूरोप-विरोधी और दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट ईयू के सदस्य देश इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी नहीं रहे. जनमत सर्वेक्षण से इशारा मिल रहा है कि वे 20 फीसदी से अधिक सीटें जीत सकते हैं. वहीं यूरोप की हिमायती पार्टियां मानती हैं कि आनेवाले सालों में ईयू को जिन मुद्दों को सुलझाना है, उनमें आप्रवासन, जलवायु संरक्षण, व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप के लिए एक मजबूत भूमिका का निर्माण करना है.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है